उत्तराखंड की खनन नीति बनी दूसरे राज्यों के लिए मॉडल, अध्ययन को पहुंची छत्तीसगढ़ की टीम

पारदर्शिता, तकनीक और सख्त निगरानी से खनन राजस्व बढ़ाने में मिली सफलता, मुख्यमंत्री धामी के निर्देशन में खनन निदेशक राजपाल लेघा के प्रयासों को मिल रही सराहना



किच्छा (दैनिक दर्पण राजमार्ग)। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में अपनी नीतिगत पहल और कार्यप्रणाली से देश के अन्य राज्यों का ध्यान आकर्षित किया है। खनन प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल, सरकारी राजस्व में वृद्धि और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए किए गए प्रयास अब दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बनते जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड की खनन व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए पहले जम्मू-कश्मीर के बाद अब छत्तीसगढ़ की खनन टीम भी राज्य के दौरे पर पहुंची है। उत्तराखंड की खनन नीति की सबसे बड़ी विशेषता इसमें तकनीक और पारदर्शिता को प्राथमिकता देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों पर खनन निदेशक राजपाल लेघा ने ऑनलाइन प्रक्रियाओं, ई-नीलामी और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इन प्रयासों का उद्देश्य खनन पट्टों के आवंटन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के साथ सरकारी राजस्व में वृद्धि करना और अवैध खनन जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। दरअसल, उत्तराखंड में खनन गतिविधियां होने के बावजूद अपेक्षित राजस्व वृद्धि एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। खनन निदेशक राजपाल लेघा ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए खनन व्यवस्था में सुधार, पारदर्शी प्रक्रियाओं और तकनीकी निगरानी को प्राथमिकता दी। इसके परिणामस्वरूप खनन क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और राजस्व बढ़ाने की दिशा में प्रयासों को गति मिली है। साथ ही अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए भी निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

खनन नीति का उद्देश्य केवल सरकारी खजाने को मजबूत करना नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का नियमानुसार और संतुलित दोहन सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए खनन क्षेत्रों की निगरानी, नियमों का पालन और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के चलते उत्तराखंड में खनन का प्रबंधन अन्य राज्यों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में यहां विकसित की जा रही तकनीक आधारित व्यवस्था दूसरे राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार पारदर्शिता, तकनीकी निगरानी, पर्यावरण संरक्षण और प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण को एक साथ लागू करके खनन क्षेत्र में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उत्तराखंड की खनन नीति का दूसरे राज्यों द्वारा अध्ययन किया जाना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ की टीम का यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि राज्य की खनन व्यवस्था को लेकर अन्य प्रदेशों में भी रुचि बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तैयार की गई नीतियों को धरातल पर उतारने में खनन निदेशक राजपाल लेघा की कार्यशैली और प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। हालांकि इस व्यवस्था की सफलता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश, पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन और निगरानी तंत्र को लगातार मजबूत करना भी जरूरी है। यदि इन प्रयासों को इसी तरह आगे बढ़ाया जाता है तो उत्तराखंड देश में पारदर्शी, तकनीक आधारित और व्यवस्थित खनन व्यवस्था का एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है।